

भारत में खाद्य सुरक्षा: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन

पूनम

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, रोहतक, हरियाणा 124001

ddangi1989@gmail.com

ज्योति

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन विभाग, मानविकी और उदार कला विद्यालय, निम्स विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान, 303121

adityagour8811@gmail.com

<u>DOI(Digital Object Identifier)</u>	<u>Article Received</u>	<u>Article Accepted</u>	<u>Article Published</u>
https://doi.org/10.5281/zenodo.22979383	21.9.2026	22.9.2026	27.9.2026

सारांश

प्रस्तुत शोध में भारत में ग्रामीण में शहरी क्षेत्र पर खाद्य सुरक्षा के बारे में अध्ययन किया गया है। भारत में खाद्य सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो देश की आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी नागरिकों को भरपूर मात्रा में पोषक तत्वों से भरपूर सुरक्षित और सस्ती खाद्य सामग्री समय पर उपलब्ध हो सके। खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं व कार्यक्रम लागू किए गए हैं, जिनका उद्देश्य देश के ग्रामीण व शहर स्तर पर खाद्य सामग्री की पहुंच सुनिश्चित करना है।

प्रस्तुत शोध में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में बताया गया है। इस अधिनियम के माध्यम से गरीब और कमजोर लोगों को खाद्य सामग्री सस्ते मूल्य पर उपलब्ध होती है। इसके तहत राशन कार्ड धारकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गेहूं और मोटे अनाज जैसे खाद्यान्न प्रदान किए जाते हैं।

प्रस्तुत शोध में ग्रामीण स्तर पर खाद्य सुरक्षा के बारे में भी अध्ययन किया गया है, जिसमें सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं लागू की गई हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य कुपोषण भुखमरी और खाद्यान्न की कमी जैसी समस्याओं को दूर करना है। प्रस्तुत शोध के माध्यम से यह बताया गया है कि केवल खाद्यान्न की आपूर्ति ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है, कि खाद्य सामग्री पोशाक सुरक्षित और सस्ती हो सरकार और समाज दोनों को मिलकर खाद्य सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाने होंगे ताकि हर ग्रामीण परिवार को उचित आहार मिल सके और कुपोषण भुखमरी जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल सके। प्रस्तुत शोध में यह बताया गया है, कि शहरों में भी खाद्य सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि शहरी क्षेत्र में अधिक जनसंख्या विविधता और सामाजिक आर्थिक असमानताएं होती हैं। खाद्य सुरक्षा का मतलब है कि सभी लोगों को पर्याप्त पोषक और सुरक्षित भोजन मिल सके खास तौर पर गरीब और वंचित वर्गों के लिए शहरों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की जाती है। जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति भुखमरी और कुपोषण का शिकार ना हो।

मुख्य शब्द: ज़मलूवतकेरू, खाद्य, कुपोषण, गरीबी

Corresponding Author

Name: Poonam

E.Mail: ddangi1989@gmail.com

Disclaimer: The opinions, interpretations, conclusions, recommendations, analyses, and statements expressed in this research article are solely those of the author(s) and do not reflect the views, policies, or positions of the Publisher, Chief Editor, Editors, Editorial Board, Reviewers, or their affiliated institutions. The author(s) are solely responsible for ensuring the originality, authenticity, and integrity of the manuscript and for ensuring that it is free from plagiarism, AI-generated content, copyright infringement, data falsification, and any other form of academic misconduct.

भूमिका

भारत में खाद्य सुरक्षा एक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक मुद्दा है, जो देश की विकासशील स्थिति में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खाद्य सुरक्षा का मतलब केवल पर्याप्त मात्रा में भोजन की पहुंच से ही नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति को पोषक सुरक्षित और सस्ती खाद्य सामग्री प्राप्त हो सके, जिससे उसका शारीरिक और मानसिक विकास सही तरीके से हो सके। भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा की स्थिति भिन्न-भिन्न प्रकार की चुनौतियां पेश करती है। भारत में खाद्य सुरक्षा केवल एक सरकारी नीति नहीं है बल्कि सामाजिक आर्थिक और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक विशेष मुद्दा है, विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी इलाकों में खाद्य सुरक्षा की स्थिति बहुत ही भिन्न होती है और इन क्षेत्रों में अलग-अलग समस्याएं उत्पन्न होती हैं ग्रामीण स्तर पर खाद्य सुरक्षा का मुख्य कारण कृषि संकट है किसान जो अपनी फसल से भोजन प्राप्त करते हैं मौसम की अनिश्चित सूखा बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण भी एक गंभीर समस्या है, जहां लोग अक्सर सिर्फ कैलोरी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन पोषण से भरपूर भोजन की कमी रहती है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और वृद्धों में यह समस्या ज्यादा देखी जाती है। सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना आदि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रयास किया जा रहे हैं।

भारत में शहरीकरण की गति तेजी से बढ़ रही है, और इसका प्रभाव खाद्य सुरक्षा पर पड़ रहा है। बड़े-बड़े शहरों में प्रवासियों, गरीबों और श्रमिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो शहरों में रहने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त भोजन और पोषण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। शहरों में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पब्लिक डि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जैसी विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया गया है। जिसे खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में सहायता मिल सके।

शोध का उद्देश्य

1. ग्रामीण और शहरी स्तर पर कुपोषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करना।
2. प्राकृतिक आपदाओं और कृषि संकट से प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना।

शोध विधि:

प्रस्तुत शोध द्वितीय स्रोतों पर आधारित है। शोध पत्र में पुस्तकों जर्नल आदि का प्रयोग किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा

भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहां के अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, इन ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा एक गंभीर विषय है, खाद्य सुरक्षा का मतलब है, प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता हो सके, ताकि उसकी शारीरिक और मानसिक सेहत बनी रहे। हालांकि भारत में खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में खाद्य सुरक्षा की स्थिति अभी भी चुनौती पूर्ण है, विशेष रूप से कृषि संकट कुपोषण और आसमान खाद्य वितरण के कारण ग्रामीण इलाकों में खाद्य सुरक्षा में कमी देखी जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा की समस्याएं:

- **कृषि संकट और प्राकृतिक आपदाएं:** भारतीय ग्रामीण क्षेत्र का अधिकतर हिस्सा कृषि पर निर्भर है। फसल उत्पादन जलवायु और मौसम स्थितियों के अनुसार यह प्रभावित होता है। सूखा, बाढ़, कीट प्रकोप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। इसे खाद्य संकट उत्पन्न होता है और ग्रामीण लोग पर्याप्त भोजन प्राप्त नहीं कर पाते।
- **गरीबी और बेरोजगारी:** ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या भी खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है। खेती में असमर्थता और श्रमिकों के लिए कम रोजगार अवसर खाद्य सुरक्षा को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग आर्थिक संकट के कारण उचित और पौष्टिक भोजन प्राप्त नहीं कर पाते।
- **खाद्य असमानता:** खाद्य असमानता एक और गंभीर समस्या है। विशेष रूप से निम्न आय वर्ग के लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता। उच्च आय वर्ग के लोग बेहतर भोजन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन निम्न वर्ग को गुणवत्ता की कमी और सीमित संसाधनों के कारण असंतोषजनक खाते आपूर्ति मिलती है।

- **कुपोषण और पोषण की कमी:** ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण की समस्या एक गंभीर समस्या है। भोजन की गुणवत्ता और विविधता की कमी के कारण लोग विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्वों की कमी का सामना करते हैं। बच्चों महिलाओं और बुजुर्गों में कुपोषण से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं, जैसे कि एनीमिया, शरीर की कमजोरी और विकास में रुकावट।

भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए खाद्य सुरक्षा के उपाय:

- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम:** 2013 में लागू किया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का एक प्रमुख कदम है। इस अधिनियम के तहत गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को सस्ती दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के तहत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से चावल, गेहूं, चीनी आदि वितरित किए जाते हैं।
- **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना:** यह योजना गरीबों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। विशेष रूप से महामारी के दौरान यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करती है। इस योजना के आधार पर सरकार मुफ्त में खाद्य वितरित करती है, जिसे खाद्य सुरक्षा में सुधार होता है।
- **कृषि योजनाएं और समर्थन मूल्य:** सरकार ने विभिन्न प्रकार की कृषि योजनाएं लागू की हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिसके तहत किसानों को सीधे बैंक खातों में सहायता राशि समय पर प्रदान की जाती है। यह योजना किसानों को खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है, और इसे खाद्य संकट की संभावना भी कम होती है। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिलता है।
- **स्थानीय खाद्य उत्पादन और कृषि विविधता:** ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्थानीय खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देना अत्यंत जरूरी है। विभिन्न कृषि प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके किसानों को अपने उत्पादन की विविधता बढ़ाने और सिंचाई की बेहतर तकनीक को प्रयोग में लाने के लिए समय-समय पर प्रोत्साहित किया जाता है। यह खाद्य आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है, और किसान भी खाद्य सुरक्षा में योगदान देते हैं।
- **पोषण और खाद्य वितरण सुधार:** ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण शिक्षा को बढ़ावा देने भी खाद्य सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण कदम है। लोगों को यह बताया जाना चाहिए, कि संतुलित आहार पोषण के महत्व को समझे। इसके साथ ही खाद्य वितरण प्रणाली में सुधार की भी आवश्यकता है, जिसे खाद्यान्न की आपूर्ति सही तरीके से जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके और भ्रष्टाचार को रोका जा सके।

शहरी क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा:

भारत में शहरीकरण के तेजी से बढ़ते प्रभाव के साथ-साथ शहरी क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण और जटिल मुद्दा बन गया है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को विभिन्न प्रकार के खाद्य सुरक्षा की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें गरीबी कुपोषण रोजगार और सुरक्षा शामिल है। शहरी क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा का मतलब है, शहरी गरीबों और वंचित वर्गों को उचित संस्था और पोषक भोजन मिलना शहरी इलाकों में औद्योगीकरण बढ़ती जनसंख्या और वैश्वीकरण के कारण खाद्य सुरक्षा की चुनौतियां भी बढ़ी है।

शहरी क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा की समस्याएं:

- **गरीबी और असमानता:** शहरी क्षेत्र में आर्थिक असमानता एक बड़ी समस्या है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को उच्च कीमतों पर खाद्य सामग्री प्राप्त करने में कठिनाई होती है। शहरी गरीबों को बढ़ती संख्या विशेष रूप से मजदूर और अन्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए खाद्य सुरक्षा की स्थिति को और भी जटिल बनाती है।
- **खाद्य आपूर्ति का असमान वितरण:** शहरी क्षेत्र में खाद्य वितरण प्रणाली की कमी और भ्रष्टाचार भी खाद्य सुरक्षा की बड़ी समस्या है। हालांकि पीडीएस शहरी गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा का एक उपाय है, लेकिन इसका कार्यान्वयन और कवरेज कई क्षेत्रों में कमजोर है।
- **कुपोषण और अस्वस्थ भोजन:** शहरी क्षेत्र में बढ़ती जनसंख्या के कारण पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ की उपलब्धता और खपत पर विशेष असर पड़ता है। गरीब वर्ग के लोग अक्सर सस्ता और कम गुणवत्ता वाला भोजन खा रहे हैं, जिसे कुपोषण की समस्या पैदा होती है, विशेष रूप से वृद्ध बच्चों और गर्भवती महिलाओं में यह समस्या अधिक पाई जाती है।

समस्याएं और खाद्य और असुरक्षा:

- 1- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम:** यह अधिनियम भारत में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गरीबों को सस्ती दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का एक विशेष और महत्वपूर्ण कदम है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से शहरी गरीबों को चावल गेहूं चीनी और अन्य खाद्य सामग्री सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाती है। यह शहरी खाद्य सुरक्षा में सुधार लाने के लिए प्रमुख उपाय है।
- 2- **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना:** कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लागू की गई, जिसके अनुसार शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीबों को मुफ्त का दान वितरित किया गया। यह योजना शहरी इलाकों में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद करती है, विशेष कर महामारी के दौरान जब दैनिक मजदूरी करने वाले लोग भोजन की कमी से जूझ रहे थे।
- 3- **कुपोषण और पोषण शिक्षा:** शहरी क्षेत्र में पोषण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित किया जा सकता है। गरीब वर्ग को पोषक आहार के महत्व के बारे में जागरूक करना और उन्हें संतुलित आहार के बारे में जानकारी देना कुपोषण को कम कर सकता है। सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा पोषण शिक्षा कार्यक्रमों की शुरुआत तेजी से की जा रही है।
- 4- **शहरी कृषि और स्थानीय उत्पादन:** शहरी क्षेत्र में शहरी कृषि को बढ़ावा देना भी खाद्य सुरक्षा का एक प्रभावी उपाय हो सकता है। यह सारे इलाकों में ताजा और पोषक खाद्य पदार्थ की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। शहरी बागवानी और छोटे खेतों में उत्पादन से खाद्य आपूर्ति की निर्भरता काफी कम हो सकती है।

खाद्य सुरक्षा में सुधार हेतु कुछ सुझाव:

❖ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत बनाना:

- **ग्रामीण क्षेत्र:** ग्रामीण क्षेत्रों में पीडीएस की पहुंच और प्रभावशीलता को सुधारने के लिए प्रयास करने चाहिए। हालांकि यह प्रणाली पहले से ही कार्यरत है, लेकिन कई इलाकों में इसकी कार्य प्रणाली और पारदर्शिता में काफी कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गरीबों को सस्ती दरों पर खाद्य सुनिश्चित करने के लिए पीडीएस की कार्य प्रणाली को मजबूत करना आवश्यक है।
- **शहरी स्तर:** शहरी क्षेत्र में पीडीएस का कवरेज बढ़ाने और इसे अधिक पारदर्शी बनाने में से शहरी गरीबों को सस्ती दरों पर खाद्य उपलब्ध हो सकता है। शहरी क्षेत्र में प्रवासी मजदूर स्लम बस्तियों और दैनिक मजदूरी करने वालों को पीडीएस के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

❖ स्थाई कृषि और स्थानीय खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देना:

- **ग्रामीण स्तर:** ग्रामीण क्षेत्रों में जैविक खेती और विविधता पूर्ण फसल प्रणाली को बढ़ावा देने से स्थानीय खाद्य आपूर्ति और बेहतर हो सकती है। किसानों को बेहतर तकनीक और उपकरण प्रदान कर उनकी उपज की क्षमता में वृद्धि की जा सकती है।
- **शहरी स्तर:** शहरी कृषि को बढ़ावा दिया जा सकता है, जैसे छत पर बागवानी सामुदायिक बाग और ऊर्ध्वाधर खेती के माध्यम से शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर ताजा और पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इन खेती पद्धतियों को अपनाना सहायक हो सकता है।

❖ पोषण शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना:

- **ग्रामीण स्तर:** ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण शिक्षा कार्यक्रमों को लागू करने से लोगों को संतुलित आहार के महत्व के बारे में विशेष रूप से जागरूक किया जा सकता है। विशेष कर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को पोषण की सही जानकारी देना आवश्यक है।
- **शहरी स्तर:** शहरी क्षेत्र में गरीब समुदायों को सस्ते और पोषाक खाद्य पदार्थों के विकल्पों के बारे में जागरूक किया जा सकता है। शहरी गरीबों को पोषण संबंधी जानकारी देने के लिए कुकिंग क्लास और पोषण कार्यशालाओं का आयोजन करके उनको जागरूक किया जा सकता है।

❖ जलवायु प्रतिरोधी कृषि पद्धतियां अपनाना:

- **ग्रामीण स्तर:** जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि उत्पादन पर असर पड़ रहा है। ऐसे में जल संवर्धन, सुखा प्रतिरोधी फसलें और अन्य जलवायु प्रतिरोधी कृषि तकनीक को बढ़ावा देने से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।
- **शहरी स्तर:** शहरी क्षेत्र में जलवायु प्रतिरोधी खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देने से ग्रामीण क्षेत्र की मदद की जा सकती है। इसके लिए शोध प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता का नेटवर्क स्थापित किया जा सकता है।

❖ सरकारी योजनाओं और नीतियों को मजबूत बनाना:

- **ग्रामीण स्तर:** खाद्य संरक्षण और परिवहन में सुधार से किसानों के स्तर पर खाद्य नुकसान को कम किया जा सकता है किसान विभिन्न खाद्य संरक्षण तारिको जैसे डिब्बा बंदी फ्रीजिंग का उपयोग करके अपने को कम कर सकते हैं।
- **शहरी स्तर:** शहरी क्षेत्र में खाद्य अपव्यय को कम करने के लिए विभिन्न जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जा सकता है। अतिरिक्त खाद्य पदार्थों को खाद्य बैंकों में दान करने से भोजन की बर्बादी को रोका जा सकता है, और इसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा जा सकता है।

निष्कर्ष:

भारत में खाद्य सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अपनी विशेष चुनौतियां प्रस्तुत करता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में खदान उत्पादन और वितरण से संबंधित समस्याएं प्रमुख हैं। वहीं शहरी क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा और गरीबी के कारण आर्थिक पहुंच में रुकावटें आती रहती हैं। इन दोनों क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विकास जल संवर्धन और महिलाओं की सशक्तिकरण जैसी पहल खाद्य सुरक्षा को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। वहीं शहरी क्षेत्र में सस्ती और पोषक खाद्य सामग्री तक पहुंच रोजगार के अवसर और पीडीएस की प्रभावशीलता में सुधार से खाद्य सुरक्षा को काफी कम किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त सरकारी योजनाओं और नीतियों का सही तरीके से कार्यान्वयन खाद्य भंडारण और वितरण अवसरंचना का सुधार और पोषण शिक्षा पर जोर देने से खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है। खाद्य अपव्यय को कम करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कृषि की स्थिरता बनाए रखने के लिए बेहतर तकनीक और उपकरणों का उपयोग जरूरी है।

अतः खाद्य सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह सभी समुदायों संगठनों और व्यक्तियों की सामूहिक प्रयासों से संभव हो सकती है। सभी स्रोत पर किए गए सुधारों और सहयोग से ही हम एक सुरक्षित समस्त और पोषक खाद्य वातावरण बना सकते हैं, जो समाज के सभी वर्गों की आवश्यकता को पूरा करने में सहायता करें।

ग्रन्थ सूची

- अग्रवाल उमेश चन्द्र, अन्तोदय योजना के माध्यम से गरीबों को खाद्य सुरक्षा नई दिल्ली, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वॉ 68, अंक 10, कुरुक्षेत्र, अगस्त 2001.
- आहूजा राम, सामाजिक समस्याएँ, जयपुर, रावत पब्लिकेशन, 2016.
- कुमार गजेन्द्र, खाद्य सुरक्षा और सरकारी प्रयास, नई दिल्ली, निर्माणभवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कुरुक्षेत्र, वॉ 0 58, अंक 5, मार्च 2012.
- अग्रवाल ए0एन0, भारतीय अर्थव्यवस्था: विकास आयाम आयोजन, नई दिल्ली, विश्वा प्रकाशन, 2003.
- अग्रवाल एम0डी0 और गुप्ता बी0पी0, सहकारिता चिंतन एवं ग्रामीण विकास सहकारिता एवं औद्योगिक नीति, रमेश पब्लिकेशन, 1995.
- कुमार एल0आर0 विश्वनाथ सिन्धी, भारत 2014, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, सूचना भवन, सी0जी0ओ0 काम्प्लैक्स, नई दिल्ली.
- कुमार पी0, व्यवसायिक परिवेश - भारत में नियोजन, नई दिल्ली महावीर पब्लिकेशन, 2004

- आलम मुक्तार, महेश्वरम, त्यागी ओओएसओ, राइट टू फूड कम्पोजन, न्यू देहली, इण्डियन सोशल इन्सटीच्यूट, 2003.
- यादव साधना, खाद्य सुरक्षा कानून से घटेगी गरीबी, नई दिल्ली, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कुरुक्षेत्र, वॉओ 57, अंक 5, मार्च 2011.
- आर्य योगेश बंधु, खाद्य सुरक्षा: वर्तमान परिदृश्य एवं भविष्य में चुनौतियाँ, नई दिल्ली, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कुरुक्षेत्र, वॉओ 50, अंक 4, फरवरी 2004.
- यंग ईओ एमओ, फूड एण्ड डवैलैवमेन्ट, लन्दन एन्ड, न्यूयार्क, टेलर एन्ड फ्रंसिज ग्रुप, 2012.
- उपाध्याय देवाशीष, फलों और सब्जियों का संरक्षण एवं विपणन, नई दिल्ली, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कुरुक्षेत्र, वॉओ 64, अंक 6, अप्रैल 2017.
- उर्मिलेश, उदारीकरण और विकास का सच, नई दिल्ली, अनामिका पब्लिकेशंस, 2010
- एस व्यास विजय, फूड सिक्योरिटी इन एशियन कन्ट्रीज, न्यू देहली, एकेडमिक फाउंडेशन, 2005.
- ओसवानी एसओआरओ, न्यूट्रीशियन एवं पार्वटी, न्यू देहली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इन इण्डिया, 2000.
- कुमार सुधीर पटेल, समकालीन दौर में खाद्य सुरक्षा योजना, नई दिल्ली, संसद मार्ग, योजना वॉओ 55, अंक 5, अक्टूबर, 2010.
- कुमार संजीव मलिक, 'खाद्य सुरक्षा के समक्ष चुनौतियाँ, नई दिल्ली, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कुरुक्षेत्र, वॉओ 55, अंक 5, मार्च 2009.
- कुमार अजय गुप्ता, भारत में खाद्य सुरक्षा: अतीत व वर्तमान, नई दिल्ली, संसद मार्ग, योजना, वॉओ 58, अंक 12, दिसम्बर 2013.
- कृष्णा एन एण्ड कृष्णा टीओएनओ, पब्लिक सुपोर्ट फॉर फूट सिक्योरिटी: द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इण्डिया, न्यू देहली, सेगा पब्लिकेशन, 2000.
- करात वृन्दा, द पीओडीओएसओएण्ड इरोडिंग सिक्योरिटी सेगा पब्लिकेशन्स, न्यू देहली, 2006.
- सिंह सत्यपाल, भारत में योजनाओं के संदर्भ में कृषि सुविधाओं का विकास, प्रतियोगिता दर्पण, अक्टूबर 2013.
- कुमार पाण्डेय अशोक, भूमंडलीय भार में भूख का सवाल, दानिक बुक प्रकाशन, वैकल्पिक आर्थिक वार्षिकी, भारत, 2009-10.
- कुमार ठाकुर अनिल एण्ड पाल कल्पना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इण्डिया, न्यू देहली, रिगल पब्लिकेशन, 2011.
- कविता एण्ड नान्दल सन्तोष, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन रुरल हरियाणा: इन इवैल्वेशन, न्यू देहली, सरुप पब्लिकेशन, 2015.
- काजमी अब्बास एण्ड सटलबर्थ पीटर, द इकोनोमिक यूटीलाइजेशन ऑफ फूड कॉ- प्रोडक्ट्स, एसओपीओ पब्लिकेशन्स, यूनाईटेड किंगडम, एसओसीओ पब्लिकेशन्स, 2013.
- कुमार केओ उदय, खाद्य सुरक्षा और मानवाधिकार, नई दिल्ली, ओमेगा पब्लिकेशन्स, 2014.
- कुमार बृजेश, खाद्य सुरक्षा की सुदृढ़ स्थिति एक चुनौती, नई दिल्ली, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कुरुक्षेत्र, वॉओ 57, अंक 5, मार्च 2011.
- कटारिया सुरेन्द्र, खाद्य सुरक्षा की दिशा में सार्थक प्रयास, नई दिल्ली, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कुरुक्षेत्र, वॉओ 57, अंक 5, मार्च 2011.
- कोचरे नवीन व मनिकान्त, भविष्य के लिए अत्यन्त आवश्यक है खाद्य सुरक्षा, नई दिल्ली, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कुरुक्षेत्र, वॉओ 57, अंक 5, मार्च 2012.
- कौशिक जगबीर, विश्व में खाद्यान्न संकट की चुनौतियाँ, नई दिल्ली, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कुरुक्षेत्र, वॉओ 55, अंक 3, सितम्बर 2009
- गुहा-खासनोविस वासुदेव, आचार्या साब्द एस एण्ड देविस बेनजामिन, फूड सिक्योरिटी: इनडीकेटरस, मेजरमेंट एण्ड इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड ओपननेस, न्यूयार्क, यूनाईटेड बाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, 2007.

- गौदा गुंटे एण्ड नागराज जी० एच०, द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द कर्नाटका: ए स्टडी साऊथरन ईकोनोमिस्ट गोल्डन जुबली, न्यू देहली, 2011.
- चन्द्र रमेश वाइदर इण्डियाज फूड पॉलिसी: फरोम फूड सिक्योरिटी टू फूड डिपराइवेशन इकोनोमिक एण्ड पॉलिटिकल विकली, वॉ० 40, अंक 11, 2005.
- चरण चंचल, द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन बिहार: प्रेजेन्ट स्केनेरियो, साऊथरन ईकोनोमिस्ट गोल्डन जुबली, नई दिल्ली, 2012.
- चौधरी बासुकी नाथ एवं कुमार युवराज, आज का भारत: अर्थ और समाज, नई दिल्ली, ओरिएन्ट ब्लैकस्वॉग प्राईवेट लिमिटेड 2013.
- चौहान श्याम सुन्दर सिंह, खाद्य सुरक्षा की दिशा में सार्थक प्रयास, नई दिल्ली, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कुरुक्षेत्र, वॉ० 57, अंक 5, मार्च 2011.
- जैन पी०के०, हंसरा बी० एस०, चक्रवर्ती के०एस०, कुरुप जयाश्री एम; ससटेनेबल फूड सिक्योरिटी, न्यू देहली, मित्तल पब्लिकेशन, 2010.
- टंकाय केशव एवं दहायत तुलसीराम, अब नहीं रहेगा कोई भूखा, नई दिल्ली, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कुरुक्षेत्र, वॉ० 60, अंक 1, नवम्बर 2013.
- दास सन्दीप, रेवामपींग द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जयपुर, आर० बी० एस० ए० पब्लिकेशन, 2010.
- द्विवेदी जितेन्द्र, जैविक खेती, खाद्य सुरक्षा की सुनिश्चितता, नई दिल्ली, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कुरुक्षेत्र, वॉ. 57, अंक 5, मार्च 2011.
- नारायण सूरज, टिकाऊ खाद्य की आवश्यकता एवं रणनीति, नई दिल्ली, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कुरुक्षेत्र, वॉ० 57, अंक 5, मार्च 2011.
- नरवाल सुनीता, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2001.
- नारबर्ग होज हैलेना, मेरी फाईट डोढ़, गोर लिक स्टेवन, ब्रीगीग द फूड इकोनोमी होम: लोकल एलटरनेटिव्स टू ग्लोबल एग्री बिजनेस, कनाडा, फेरनवुड पब्लिकेशन, 2002.
- पारिख किरीट एस०, खाद्य सुरक्षा कानून-क्या भूख और कुपोषण का खात्मा कर पाएगा, नई दिल्ली, योजना भवन, संसद मार्ग, योजना, वॉ० 58, अंक 12, दिसम्बर 2013.
- प्रसाद सिंह अभय, समकालीन भारत में विकास की प्रक्रिया और सामाजिक आन्दोलन, नई दिल्ली, ओरिएन्ट ब्लैकस्वॉग, 2015.
- बैनर्जी अमलेश, फूड सिक्योरिटी एण्ड पी.डी०एच. टुडे: सक्सैस एण्ड फेलियर, न्यू देहली, कनिष्का पब्लिशर्स, 2004.
- मोदी के० एम०, खाद्य सुरक्षा: चुनौतियाँ और समाधान, नई दिल्ली, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कुरुक्षेत्र, वॉ० 58, अंक 5, मार्च 2012.
- मिश्रा एस० के० एण्ड पुरी वी०के०, इण्डियन इकोनोमी, नई दिल्ली, हिमालया पब्लिकेशन, 2011.
- यादव संगीता, बचाना होगा हर दाना: खाद्य सुरक्षा पर प्रगतिशील किसानसे साक्षात्कार, नई दिल्ली, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कुरुक्षेत्र, वॉ० 57, अंक 1, नवम्बर 2012.
- मलिक जगपाल सिंह, बढ़ता कृषि उत्पादन: एक परिदृश्य, नई दिल्ली, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय कुरुक्षेत्र, वॉ० 61, अंक 11, सितम्बर 2015.
- रायजादा बी० एस० एवं शर्मा वंदना, शिक्षा में अनुसंधान के आवश्यक तत्त्व, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2013.
- लाल आर० एण्ड स्टेवर्ट ाबी० ए०, सिक्योरिटी एण्ड सॉयल कालिटी लंदन एण्ड न्यूयार्क, टेलर एण्ड फ्रांसिज ग्रुप, 2010.
- श्री वास्तव अर्चना, भूख की भ्यावह होती आग, नई दिल्ली, योजना भवन, संसद मार्ग, योजना, वाल्यूम 55, अंक 5, अक्टूबर 2010

-
- शर्मा जी0 एल0, सामाजिक मुद्दे, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2015.
 - शिवा वन्दना एण्ड बेदी गीताजंलि, न्यूट्रीशियन एवं पार्वटी, न्यू देहली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस इन इण्डिया, 2002.
 - शिवा वन्दना, सीड सोवरजिटी: वूमैन इन दा वैनगार्ड, न्यू देहली, वूमैन अनलिमिटेड पब्लिकेशन, 2015.
 - सिंह विरेन्द्र, खाद्य सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां एवं निदान, नई दिल्ली, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कुरुक्षेत्र, वॉ0 60, अंक 1, नवम्बर 2013.
 - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
 - मिश्र नन्दलाल, कुपोषण से लड़ाई: कठिन डगर, योजना, नई दिल्ली, वॉ0 62, अंक 05, मई 2018.

